



टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में 7 रन से जीत दर्ज कर 13 साल बाद एक बार फिर भारत टी-20 क्रिकेट का सरताज बन गया है। बारबोडोस में शनिवार को खेले गये मुकामले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को अंतिम गेंद तक चले रोमांचक मुकामले में 7 रन से हरा दिया। इस जीत में विराट कोहली के 76 रनों का बड़ा योगदान रहा, इस प्रदर्शन के लिए उन्हें “प्लेयर ऑफ द मैच” चुना गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुये भारतीय टीम ने 176 रन बनाये। भारत की शुरुआत काफी खराब रही, लेकिन बाद में अक्षर पटेल और विराट कोहली ने बड़ी साझेदारी कर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुँचाया। पूरे टी-20 टूर्नामेंट में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंद से बहुत ही शानदार योगदान दिया। बुमराह को उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए “प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट” चुना गया। पहली बार किसी गेंदबाज को यह सम्मान मिला है। भारत ने 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था तथा उससे पहले वर्ष 2007 में टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। इस प्रकार भारत दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना है।

बंगाल के राज्यपाल ने मु.मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मान हानि का मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में

ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि, महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि, वे राज भवन जाने से डर रही हैं, राज भवन में चल रही “गतिविधियों” के कारण

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जून। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत के बाद राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने उनके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा कि एक महिला उनके पास यह शिकायत लेकर आयी थी कि राजभवन में चलने वाली गतिविधियों को लेकर उन्हें वहाँ जाने से डर लगता है।

सूत्रों ने बताया कि मोदी मंत्रिमंडल के सबसे ताकतवर मंत्री ने राज्यपाल बोस को अनुमति दी है कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोर्ट में घसीटें।

ममता बनर्जी की टिप्पणियों को लेकर बोस ने आज सुबह उनकी आलोचना करते हुए कहा कि यह जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे किसी की गलत एवं निंदात्मक छवि पेश न करें। सूत्रों ने बताया कि बंगाल के राज्यपाल ने तृणमूल कांग्रेस

■ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि, राज भवन में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही एक महिला कर्मचारी ने उनसे यह शिकायत की है कि, राज्यपाल आनन्द बोस ने उस महिला कर्मचारी का “यौन शोषण” भी किया और इस शिकायत के बाद अहम कोलकाता पुलिस इस यौन शोषण प्रकरण की जाँच कर रही है।

(टी.एम.सी.) के कुछ नेताओं के खिलाफ भी ऐसी ही गलत बयानबाजी करने को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है।

बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में हुई एक प्रशासनिक मीटिंग के दौरान दावा किया था कि “महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन में हुई हाल की घटनाओं के मद्देनजर उन्हें वहाँ जाने से डर लगता है।

राजभवन में संविदा पर लगी एक महिला कर्मि ने गत 2 मई को बोस पर कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी एक जाँच शुरू की थी।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पार्टी के साथियों के साथ वर्ष 1998 में धरना दिया था और मांग की थी कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने और एक मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट के बिना शपथ दिलवाने में अपनी कथित संदिग्ध भूमिका के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रोमेश भण्डारी को पद से हटाया जाए। वर्ष 2016 में ही, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के राज्यपालों की भूमिका पर तब प्रसंगिक चर्चा हुई थी, जब केन्द्र सरकार ने उनके सिफारिश पर इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

13 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जे.पी. राजखोवा के निर्णय को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था। राजखोवा ने राज्य के विधानसभा 14 जनवरी से पहले 16 दिसम्बर से शुरू करने का निर्णय लिया था, जिससे इस सीमाई राज्य में असंतोष फैल गया और उसकी वजह से यहाँ गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर जस्टिस खेहर के नेतृत्व वाली पाँच जजों की एक बैंच ने आदेश दिया कि 15 दिसम्बर 2015 को जो स्थिति थी उसी को वापस से बहाल किया जाए। इस आदेश ने भाजपा समर्थित एवं मुख्यमंत्री खलीको पुल के नेतृत्व वाले कांग्रेस की बागी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही कांग्रेस नेतृत्व वाली मुख्यमंत्री नबम तुकी सरकार को सत्ता में वापसी की।

उत्तराखण्ड के बाद, शीर्ष अदालत ने अपने एक निर्णय में भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार द्वारा किए जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयराम रमेश ने नीतीश व चंद्रबाबू नायडू को चुनौती दी

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जून। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को जनता दल (यू.) द्वारा पारित संकल्प का जिक्र किया जिसमें बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की केन्द्र सरकार से मांग की गई है ताकि केन्द्रीय सहायता

■ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि, जद (यू) नेता नीतीश, तेलुगु देसम नेता चंद्रबाबू नायडू बताएं कि, वे अपने राज्यों के लिए केन्द्र से विशेष दर्जा मानाने से क्यों कतरा रहे हैं।

मिल सके। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य मंत्रिमण्डल में ऐसा प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव पारित करने का साहस दिख सके हैं। उन्होंने कहा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री इस बात पर अमल करेंगे। जयराम ने एक्स पर पोस्ट कर टी.डी.पी. से भी उसकी नई पारी में स्टैण्ड जानना चाहा है। उन्होंने कहा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडू में “नीट” परीक्षा को मैडिकल कॉलेज में प्रवेश का आधार बनाने का विरोध दर्ज करवाया

तमिलनाडू के मु.मंत्री स्टालिन ने इस मन्तव्य से विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करवाया

-लक्ष्मण वेंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 जून। नीट के खिलाफ तमिलनाडू की आवाज अब देश की आवाज बन गई है, यह बात कही है तमिलनाडू के मुख्यमंत्री ने जो मैडिकल पाठ्यक्रम में प्रदेश के इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के खिलाफ तीसरी बार प्रस्ताव ला रहे हैं और उन्होंने इस परीक्षा को खत्म करने की मांग की जो सब राज्यों पर लाद दी गई है।

अब नीट परीक्षा में एक के बाद एक पेपर लीक की घटना और भारी फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद तमिलनाडू मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा पर प्रतिबंध की मांग अब पूरे देश से आ रही है और टैस्टिंग एजेंसी को लेकर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। लेकिन तमिलनाडू जैसे राज्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस टेस्ट के कारण ग्रामीण व निर्धन

■ मु.मंत्री स्टालिन ने प्रस्ताव पारित करने के पक्ष में तर्क दिया कि, तमिलनाडू के ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन विद्यार्थियों के लिये मैडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाना अत्यन्त मुश्किल हो गया है। स्टालिन ने यह भी दावा दिलाया कि, तमिलनाडू की विधानसभा ऐसे प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिये भेज चुकी है।

■ स्टालिन के अनुसार, नीट परीक्षा में पेपर लीक व भ्रष्टाचार की घटनाओं के कारण राहुल गाँधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी नीट परीक्षा का सिस्टम खत्म करने की हमारी मांग के समर्थन में आ गये हैं।

परिवारों को मैडिकल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। तमिलनाडू सरकार पहले भी दो बार नीट पर प्रतिबंध की मांग का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। शुक्रवार को तीसरा प्रस्ताव पारित किया गया। रोचक बात यह है कि इस दौरान भाजपा ने तो सदन से वाँक आउट किया पर उसकी

गठबंधन सहयोगी पार्टी पी.एम.के. ने द्रमुक के प्रस्ताव का समर्थन किया।

अनाद्रमुक अनुपस्थित रही क्योंकि इसके सभी विधायकों को शराव दुर्घातिका पर हंगामा करने के कारण निलम्बित कर दिया गया था। तमिलनाडू (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लद्दाख: अभ्यास के दौरान नदी पार कर रहे सेना के 5 जवानों की मौत

लद्दाख, 29 जून। लद्दाख में सेना के जवानों के एक अभ्यास के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में टैंक के साथ जवान अभ्यास कर रहे थे तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया तेज बहाव में पाँच जवान बह गए। जानकारी

■ नदी में टैंक के साथ जवान अभ्यास कर रहे थे तभी अचानक जलस्तर बढ़ गया, तेज बहाव में पाँच जवान बह गए।

के मुताबिक एक शव ही बरामद किया जा सका है। वहीं बाकी के जवानों के शव भी अब तक नहीं मिले हैं। नदी से टी-72 टैंक को निकाला गया है। घटना एलएसी के पास ही न्योमा चुशुल इलाके की है। बताया गया कि रक्षा अधिकारी टैंक को नदी पार कराने की एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी अचानक नदी में सैलाब आ गया। पाँच जवानों की मौत के अलावा कई के घायल होने की भी सूचना है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

युवाओं के हितों पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा: मु.मंत्री भजनलाल

राज्य स्तरीय “मु.मंत्री रोजगार उत्सव” में मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने भी टीचर की नौकरी की बहुत कोशिश की थी

■ मुख्यमंत्री ने कहा, नियुक्ति पत्र मिलने पर परिवार के मन में कैसा भाव आता है हम जानते हैं, हम भी परिवार में रहते हैं।

■ मुख्यमंत्री शर्मा ने शनिवार को मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित, पहले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को संबोधित किया।

■ कार्यक्रम में नौकरी हासिल करने वाले कई नए कार्मिकों ने मु.मंत्री का आभार जताया।

■ कार्यक्रम में सभी जिलों के 20,000 से ज्यादा नवनि्युक्त अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

■ रोजगार उत्सव में, कौशल नियोजन व उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, इसी विभाग के राज्यमंत्री के.के. विश्वाँ, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, चिकित्सा सचिव शुभासिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

■ कई जिला मुख्यालयों से नए कार्मिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कार्यक्रम से जुड़े।

सरकारी नौकरियों के सुनहरे अवसर भी प्रदान कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनि्युक्त राज्य कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उत्कृष्ट राज्यकार्य के लिए प्रेरित किया। साथ ही, सभी जिला मुख्यालयों से जुड़े नवनि्युक्त कार्मिकों

से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से 20 हजार से अधिक नवनि्युक्त अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में निर्यात रूप से “मुख्यमंत्री

रोजगार उत्सव” आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर रही है। शर्मा ने कहा कि, प्रदेश में रोजगार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



प्रदेश में पहली बार “मुख्यमंत्री रोजगार महोत्सव” आयोजित हुआ। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों से राजकीय सेवाओं में नवनि्युक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बाँटे।